



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2001/भाद्र 6, 1923

No. 614]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2001/BHADRA 6, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2001

का.आ. 829(अ).— राष्ट्रपति, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 23 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना सं० का० आ० 324 (अ), का० आ० 325 (अ), का० आ० 326 (अ), का० आ० 327 (अ), और अधिसूचना सं० का० आ० 386 (अ) और का० आ० 387 (अ) तारीख 3 मई, 1994 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसरण में, जो संविधान के अनुच्छेद 243 ब और अनुच्छेद 243 यख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम 1994 (1994 का 1) की धारा 186, लक्षद्वीप पंचायत विनियम 1994 (1944 का 4) की धारा 86, दादरा और नागर हवेली ग्राम पंचायत विनियम 1965 (1965 का 3) की धारा 46 क, गोवा, दमन और दीव पंचायत विनियम 1962 (1962 का 9) की धारा 45क, अंदमान और निकोबार द्वीप नगर पालिका विनियम 1994 (1994 का 5) की धारा 72 तथा गोवा दमन और दीव नगर पालिका अधिनियम 1968 (1968 का 16) की धारा 143क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंदमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्त आयोग (जिसे इसमें इसके अधीन आयोग कहा गया है) गठित करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|----|---------------------|---------|
| 1. | श्री अशोक कुमार | अध्यक्ष |
| 2. | श्री बीरेन्द्र सिंह | सदस्य |
| 3. | श्री आर.एस. सेठी | सदस्य |

2. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है छः मास की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3 आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिशें करेगा ।

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनके अपनी पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच, संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमो का वितरण ;

(ख) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली, की पंचायतों और नगर पालिकाओं को समनुदेशित की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी ;

(ग) भारत की संचित निधि में से अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली की पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान ;

(घ) अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली की पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपाय और उनके संसाधन आधार का विस्तार करने के लिए संसाधन और प्रोत्साहन उत्पन्न करने के लिए उनकी क्षमता और उत्तरोत्तर सुधार के संवर्धन के लिए अपेक्षित अध्युपाय ;

4. आयोग अपनी सिफारिशें करने में, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित का ध्यान रखेगा :-

(क) प्रथमतः केवल यही उद्देश्य नहीं है कि अंदमान और निकोबार द्वीप, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप और उनकी पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व लेखे में प्राप्तियों और व्यय का संतुलन हो, तत्पश्चात् ऐसी रीति में जिससे कि पूंजी विनिधानों के लिए पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न हो ;

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली योजनाओं स्कीमों के संबंध में पूंजी आस्तियों और अनुरक्षण व्यय का अनुरक्षण और रख-रखाव और वे मानदंड जिनके आधार पर विनिर्दिष्ट रकमों की पूंजी के अनुरक्षण के लिए सिफारिशें की जाती हैं ;

(ग) वाणिज्यिक उपक्रमों, विद्युत परियोजनाओं, पब्लिक सैक्टर, उद्यमों आदि में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा विनिधानों के संबंध में युक्तियुक्त प्रत्यागम सुनिश्चित करने की आवश्यकता ;

(घ) आयोग विद्यमान संसाधनों पर आधारित पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व संसाधन का और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा 2001-2002 से 2009-2010 तक की अवधि के लिए जो राष्ट्रीय वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप है, उद्ग्रहीत या विनियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित करें, शुल्कों, पथकों और फीसों का निर्धारण करेगा। आयोग इस अवधि के लिए व्यय आवश्यकताओं और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले विकास के व्यापक क्षेत्रों का भी निर्धारण करेगा ;

(ङ) आयोग, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली की दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाओं और विकासात्मक लक्ष्यों, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित विनिधानों के आदेश और अपेक्षित संसाधनों के लिए संभावित संसाधनों पर भी विचार कर सकेगा ;

(च) व्यय में दक्षता और मितव्ययिता से संगत बेहतर राज वित्तीय प्रबंध के लिए क्षेत्र ;

(छ) आयोग उपलब्ध किए गए वित्तीय परिचयों के लिए परियोजनाओं या स्कीमों (योजनागत और योजनेत्तर) दोनों की वास्तविक प्रगति को मानीटर करने के लिए एक पद्धति भी विकसित कर सकेगा ;

5. आयोग, पूर्वोक्त विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करने में, ऐसे सभी मामलों में जहां जनसंख्या पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए या करें, शुल्को, पथकों, फीसों आदि के निर्धारण के लिए कारक माना जाता है वहाँ उसे अद्यतन जनसंख्या आकड़ों को अंगीकार करेगा ।

6. आयोग, पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर अपनी रिपोर्ट, उसके गठन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर उपलब्ध करा देगा और आयोग उस आधार को जिस पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं, उपदर्शित करेगा तथा प्राप्तियों और व्यय के पंचायतवार और नगरपालिकावार प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा ।

[फा. सं. यू-13034/16/2001-एएनएल]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2001

S.O. 829(E).— In pursuance of articles 243-I and 243-Y of the Constitution, read with the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs numbers S.O. 324(E), S.O. 325(E), S.O. 326(E), S.O. 327(E), all

dated, the 23rd April, 1994 and S.O. 386(E) and 387 (E) dated, the 23rd May, 1994, issued in exercise of the powers conferred by articles 243 L and 243 ZB of the Constitution, and in exercise of the powers conferred by section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994 (1 of 1994), section 86 of the Lakshadweep Panchayats Regulation, 1994 (4 of 1994), section 46A of the Dadra and Nagar Haveli Village Panchayats Regulation, 1965 (3 of 1965), section 45 A of the Goa, Daman and Diu Village Panchayats Regulation, 1962 (9 of 1962) and section 72 of the Andaman and Nicobar Islands Municipal Regulation, 1994 (5 of 1994) and section 143A of the Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968 (16 of 1968), the President is pleased to constitute a Finance Commission for the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep (hereinunder referred to as the Commission) consisting of the following persons, namely :-

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1. | Shri Ashok Kumar | Chairman |
| 2. | Shri Virendra Singh | Member |
| 3. | Shri R.S. Sethi | Member |

2. The Chairman and other members of the Commission shall hold office for a period of six months from the date on which the Chairman assumes his office.

3. The Commisison shall review the financial position of the Panchayats and Municipalities and make recommendations relating to the following matters :

- (a) the distribution between the Union territory Administrations of the Andaman and Nicobar Islands,

Lakshadweep, Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli and their respective Panchayats and Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the respective Union territory Administrations ;

- (b) the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the Panchayats and Municipalities of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli ;
- (c) the Grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli from the Consolidated Fund of India; and
- (d) the measures needed to improve the financial position of Panchayats and Municipalities in the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli; and the measures required to promote progressive improvement in their capacity to generate resources and incentives to enlarge their resource base.

4. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to:

- (a) the objective of not only balancing the receipts and expenditure on revenue account of the Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar

Haveli and Lakshadweep in the first instance and their Panchayats and Municipalities; thereafter, in a manner that sufficient surplus is generated for capital investments;

- (b) the maintenance and upkeep of capital assets and maintenance expenditure on plan schemes to be completed during the 10th Five Year Plan period and the norms on the basis of which specified amounts are recommended for the maintenance of the capital;
- (c) the need for ensuring reasonable returns on the investments by the Panchayats and Municipalities in commercial undertakings, power projects, public sector enterprises, etc.;
- (d) the Commission shall assess the revenue resource of the Panchayats and Municipalities based on the existing resources and taxes, duties, tolls and fees proposed to be levied or appropriated by the Panchayats and Municipalities for the period 2001-2002 to 2009-2010, to coincide with the period of the National Finance Commission. The Commission shall, also, assess the expenditure needs for this period and the broad areas of development to be undertaken by the Panchayats and Municipalities;
- (e) the Commission may also consider the long term perspective plans and developmental goals of the Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, the order of investments required to achieve these goals and the possible sources for the required resources;

- (f) the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in expenditure;
- (g) the Commission may also evolve a system for monitoring physical progress of projects or schemes (on both plan and non-plan sides) against financial outlays made available.

5. In making its recommendations on the various matters aforesaid, the Commission shall adopt the latest population figures in all cases where population is regarded as a factor for providing grants-in-aid or for the assessment of taxes, duties, tolls, fees etc. to the Panchayats and Municipalities.

6. The Commission shall make its report available within a period of six months, from the date of its constitution, on each of the matters aforesaid; and the Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its finding and make available the Panchayat-wise and Municipality-wise estimates of receipts and expenditure.

[F.No. U-13034/16/2001-ANL]
P. K. JALALI, Jt. Secy.

